PROPOSED PUBLIC ISSUE OF GREEN BOND FOR 60 MW AC/ 66.95 DC CAPTIVE SOLAR PROJECT

A GREEN INITIATIVE BY:
INDORE MUNICIPAL CORPORATION

A STEP TOWARDS FIRST CARBON NEUTRAL CITY OF INDIA

Glimpses of 1st Muni Bond Issue by the IMC on its listing at NSE dated 24th July 2018

16 THE ECONOMIC TIMES

Indore City Breaks New Fiscal Ground

Urbanising India needs a municipal bond market

It is one small step in diversifying the instruments available in the debt market, but a significant stride for fuelling urbanising India's engines of growth: our extant and future cities. The recent maiden debt listing of municipal bonds, or munis, on the NSE, of Indore Municipal Corporation, is path-breaking in that it creates a market for municipal bonds. Indore and a few other urban bodies in Madhya Pradesh reportedly plan to raise ₹1,200 crore via munis. There's a huge resource gap nationally when it comes to municipal bodies, and munis can be a viable financing option for well-structured urban development projects. Provided, local governments have the fiscal capacity to service the bonds they issue.

In fast urbanising India, the combined revenue receipts of all municipalities add up to under ₹1,50,000 crore, less than 1% of GDP, with less than a third of the funds locally raised. Estimates suggest that the investment requirement is far higher, over 2% of GDP annually. The way forward is to use urban planning tools to renew and expand our cities, improve neighbourhoods and increase property values. The policy focus needs to be to boost municipal revenues from property tax collections, reasonable user charges and shares in the taxes collected by state governments. Besides, given the huge infrastructural deficit, say, for urban public transport, solid waste management and sewerage treatment, munis can provide stable long-term returns to create energy-efficient and climate-friendly infrastructure. But, in tandem, we need transparency in municipal finances and standardised norms for budgeting and disclosure.

There are over 4,000 urban local bodies nationally, and over 160 municipal corporations. These need capacity building as well as political reform and empowerment, complete with participative democracy in local government, so that there is the necessary political will for creating and running efficient towns and cities, to enhance liveability, creativity and economic output. Future prosperity depends on it.

ABOUT PROJECT – 60 MW CAPTIVE SOLAR PROJECT

- At present, about Rs. 25 crore every month is spent on electricity cost by the Indore Municipal Corporation on pumping and supply of drinking water.
- To reduce the said cost, Indore Municipal Corporation is setting up a 60 MW solar project at Jalud Pumping Station at a cost of Rs. 305 crores. The cost of this project will be met through Public Issue of Green Bonds.
- After the successful issuance of the country's first Private Placement - Muni Bonds on the National Stock Exchange, now it is proposed to raise the funds through a Public Issue. This will be the first green bond in the country to be issued by a municipal corporation through a public issue.
- Rs. 20 crore interest subsidy will be received from the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA), Government of India, which is approximately 1.5%.
- A grant of Rs. 42 crore has been sanctioned by MNRE, Government of India, in the form of VGF for this project.

एनएसई-बीएसई में लिस्टेड बांड 11 से 14 फरवरी तक बिक्री के लिए खुलेंगे

ग्रीन बांड के लिए मुंबई में रोड शो, ब्रोकर मीट-वेबिनार में महापौर ने दी जानकारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. जलूद में बनने वाले 60 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुंबई में रोड शो किया। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड रूम में ब्रोकर मीट तथा वेबिनार के जरिए महापौर ने ग्रीन बांड के बारे में जानकारी दी।

22 फरवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे ... खुलेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए मुंबई में नगर निगम ने आयोजन किया था। महापौर और अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह सहित अन्य अफसरों ने स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरों से बांड के बारे में बात की। रोड शो और वेबिनार के दौरान महापौर ने बताया कि बांड का मूल्य 1 हजार रुपए प्रति बांड है। इसमें इफेक्टिव कूपन रेट 8.25 प्रतिशत तथा प्रभावी ...

इंदौर है दूसरे नंबर पर

देश में पहला ग्रीन बांड गाजियाबाद नगर निगम ने अप्रेल, 2021 में जारी किया था। उसे 150 करोड़ के निर्गम के मुकाबले 401 करोड़ ...

बांड की विशेषताएं

1000	8.25%	08
प्रति बांड मूल्य	अर्धवार्षिक कूपन साइज	वर्ष की अवधि

- बांड चार भाग में ट्रेडेबल कमोडिटी है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में की जाएगी। ट्रेडेबल कमोडिटी होने के कारण निवेशकों को बांड के ...

एसटीआरपीपी डी 8 साल में परिपक्व होगा। पहले से तीसरे ...

IMC promotes its Green Bond in Mumbai

Indore: Indore Municipal Corporation (IMC) on Monday organised a roadshow in Mumbai to promote its Green Bond meant to be listed on National Stock Exchange (NSE) to raise funds of Rs 244 crore for a mega solar power plant mooted to reduce its monthly power consumption.

Mayor Pushyamitra Bhargava, who accompanied by Indore Smart City Development Limited (ISCDL) CEO Divyank Singh, was in Mumbai to promote Green Bond said, "During the day-long event, we held a press conference in NSE office before organizing a meeting with the potential investors and a we...

The IPO can be listed ...

Private Limited ("... tings") with 'IND A... le' and CARE Ratin... ted ("Care Rating... 'CARE AA; Stable'". The bond is mean... IMC ...

size is Rs 122 crores with option to retain oversubsc... tion i.e. Green Shoe option to Rs 122 crores and aggr... ting up to Rs244 crores. Th... ce value of each bond ... is Rs1,000 while the min... application amount ...

ग्रीन बॉण्ड के लिए मुंबई में रोड शो हुआ, कल इंदौर में होगा, 10 को आएगा पब्लिक इशू

पानी पर सालाना 250 करोड़ का बिजली खर्च, सोलर प्लांट से 50 करोड़ बचाएंगे

भास्कर संवाददाता | इंदौर

...जना के दूसरे चरण के तहत ... लगने वाले 60 मेगावॉट के ... प्लांट के लिए नगर निगम 10 ... ब्लिक इशू जारी करने जा रहा ... जों के लिए 244 करोड़ की ... लिए पहली बार कोई नगर ... री कर रहा है। इसके जरिए ... की खपत पर खर्च होने ... 4 करोड़ रुपए निगम ... एक साल में 45 से ... म खर्च होंगे। यह पैसा ... र्च हो सकेगा। पानी ... म 250 करोड़ रुपए ... है।

...ख यूनिट ...न होगा

...लाख यूनिट का ...जूदा दर और ...गत के बाद ...ज की राशि ...र्च हटाने के ... रुपए की ... भुगतान ...तान की ... के ब्याज ... 244 करोड़ का ऋण ...ना होगा। इसके लिए 25-25% राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। तीन साल में 25 प्रतिशत यानी 61 करोड़ का ऋण चुकाया जाएगा। इसके ...

जो पैसा बचेगा, वह अन्य परियोजनाओं पर खर्च कर सकेंगे

60	02	90	8.40%
मेगावॉट का सोलर प्लांट लगेगा जलूद में	लाख 70 हजार यूनिट बिजली बनेगी हर दिन	हजार कार्बन क्रेडिट मिलेंगे हर साल	की दर से निवेशकों को रिटर्न करेगा निगम

जलूद में जहां पंपिंग स्टेशन है, उसके पास ही नगर निगम सोलर पॉवर प्लांट लगाएगा।

244 करोड़ के शेयर बाजार में आएंगे

ग्रीन एनर्जी बॉण्ड के जरिए 244 करोड़ के शेयर बाजार में लेकर आ रहे हैं। इसकी फेस वैल्यू एक हजार रुपए होगी। सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ दिव्यांक सिंह मुंबई पहुंचे। शाम को महापौर का रोड शो हुआ। 8 फरवरी को इंदौर में रोड शो होगा। भार्गव ने ...

देश के लिए क्लाइमेट फाइनेंस का यह दमदार मॉडल : एक्सपर्ट

एन्वायरमेंटल डिफेंस फंड के चीफ इंडिया एडवाइजर हिषम मंडल कहते हैं देश के लिए क्लाइमेट फाइनेंस का यह दमदार मॉडल है। इंदौर ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे देश के अन्य नगर निगमों को भी अपनाना चाहिए। इस बॉन्ड से आर्थिक बचत के साथ ही पर्यावरण संबंधी लाभ भी हासिल होंगे। इनमें कार्बन क्रेडिट्स के जरिये आमदनी ...

स्वच्छता के बाद अब देश में पहली बार ग्रीन बॉन्ड

जलूद संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाएंगे

खुलासा फर्स्ट... इंदौर

इस तरह पूरी कैपिटल हो जाएगी वापस

निगम के ग्रीन पब्लिक बॉन्ड को चार हिस्सों में बांटा गया है। इसके तहत खरीदार को कुल बॉन्ड का 25 प्रतिशत हिस्सा तीसरे व शेष राशि इसी अनुपात में तीसरे, पांचवें व नौवें साल में मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि कोई एक लाख रुपए का बॉन्ड खरीदता है तो उसे 25 हजार रुपए बॉन्ड जारी होने के तीन साल बाद मिलेंगे। पांचवें, सातवें और नौवें साल शेष 25 हजार रुपए मिलेंगे। इस प्रकार बॉन्ड होल्डर को निर्धारित अंतराल में राशि मिलेगी और आखिर में पूरी कैपिटल वापस हो जाएगी। बॉन्ड होल्डर को ग्रीन बॉन्ड पर ब्याज 8.25 प्रतिशत की दर से छह माह में मिलने लगेगा।

Mayor holds roadshow in Mumbai to promote IMC's green bond

OUR STAFF REPORTER
city.indore@fpj.co.in

Mayor Pushyamitra Bhargav held a roadshow and a webinar and also interacted with potential investors in Mumbai to promote the ...

turn... bagg... est ... con... pop... is d... da... A... IM... of ... to ... fro... is ... po... th...

मुंबई में महापौर भार्गव ने एनएसई व निवेशकों के साथ की बैठक

ग्रीन बांड लाने वाला देश का पहला निगम बनेगा इंदौर

मुंबई के नेशनल स्टाक एक्सचेंज में सोमवार को ग्रीन बांड जारी होने से पहले रोड शो हुआ। इसमे महापौर ने निवेशकों से चर्चा की। ●सौजन्य : नगर निगम

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। इंदौर नगर निगम 10 फरवरी को ग्रीन बांड जारी ...

निगम का ग्रीन बांड

बांड पब्लिक इशू: 244 करोड़ रुपये

ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशु जारी करने वाला इंदौर देश का पहला शहर

महापौर ने ग्रीन मुबई में किया रोड शो

इंदौर. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदौर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जारी किये जा रहे ग्रीन बॉन्ड के संबंध में जानकारी दी. इसके पश्चात ब्रोकर मीट तथा वेबिनार के माध्यम से भी महापौर ने ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इशु जारी करने के संबंध में जानकारी दी. इस अवसर पर अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह व अन्य उपस्थित थे.

गौरतलब है कि इंदौर ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशु जारी करने वाला इंदौर देश का पहला शहर है, जिसमें ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. इस ब्रान्ड का मुल्य राशि रूपये 1 हजार प्रति बॉन्ड है, जिसमें इफैक्टिव कूपन रेट 8.25 प्रतिशत तथा प्रभावी वार्षिक दर 8.41 प्रतिशत है, जिसको एए प्लस व एए की रेटिंग प्राप्त बॉन्ड है ...

यह ग्रीन बॉन्ड 10 फरवरी से पब्लिक के लिये जारी किये जाएंगे, उक्त बॉन्ड 14 फरवरी को बंद हो जाएंगे.

प्रस्तावित ग्रीन बांड का पब्लिक इशु

इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा राशि रू. 244 करोड़ के ग्रीन बांड का पब्लिक इशु जारी किया जा रहा है. ग्रीन बांड का पब्लिक इशू होने के पश्चात इंदौर नगर पालिक निगम ऐसा करने वाला भारत का प्रथम नगरीय निकाय होगा. कोई भी आम इंसान सीधे भागीदारी करते हुए बांड की खरीदी कर सकता है एवं पर्यावरण सहयोगी गतिविधियों में सहायता कर सकता है.

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की गतिविधि

यह एक नगरीय वित्तीय नवाचार होने के साथ ही सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधि है. जनता कि भागीदारी से जमा कुल राशि रू. 244 करोड़ से 60 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जलूद (जिला-खरगोन) में लगाया जाएगा, जिससे प्रतिमाह राशि रू. 4-5 करोड़ की बिजली खर्च में बचत इंदौर को होगी.

बांड की प्रमुख विशेषताएं

- बांड का मूल्य राशि 1,000 रुपए प्रति बांड
- कूपन साइज: 8.25 प्रतिशत अर्ध वार्षिक
- परिपक्वता अवधि (मैचुरिटी) : 8 वर्ष

चार भाग में ट्रेडेबल कोमोडिटी

यह बांड चार भाग में ट्रेडेबल कोमोडिटी है, जिसकी लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में की जाएगी. ट्रेडेबल कोमोडिटी होने के कारण आमजनो (निवेशकों) को बांड के ट्रेड के माध्यम से भी लाभ होगा. इंदौर नगर पालिक निगम को ट्रेडिंग हेतु एए एवं एए* रेटिंग दी गयी है.

इस तरह होगा प्रचार-प्रसार

बांड की जानकारी 3 से 9 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक निवेशकों को दी जाएगी. इसके अतिरिक्त प्रचार प्रसार हेतु देश के विभिन्न शहरों रोड शो का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम के अंतर्गत 6 फरवरी को मुंबई में रोड शो और निवेशकों के साथ बैठक एवं वेबिनार, 8 फरवरी को इंदौर में रोड शो और निवेशकों के साथ बैठक एवं वेबिनार, 8-9 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत प्रचार प्रसार, 10 फरवरी को पब्लिक इशु क्रय हेतु खुलेगा. 11-14 फरवरी तक पब्लिक इशु क्रय हेतु खुला रहेगा. 14 फरवरी को पब्लिक इशु निवेशकों हेतु बंद होगा. 22 फरवरी के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्टि समारोह (लिस्टिंग सेरेमनी) होगी.

ABOUT THE PUBLIC ISSUE OF GREEN BONDS

- The proposed Green Bond is AA+ rated by India Ratings and AA by Care Ratings, which is considered the best in this category.
- Every bond divided into 4 independent tradable scripts payable in equal amount in 3rd, 5th, 7th & 9th years. Enhance the liquidity across & benefits of market trends.
- The public issue Opened on 10th February 2023 and closed on 14th February 2023.
- The listing ceremony held on 22nd or 23rd February 2023.
- Coupon rate is 8.25% with half yearly payment thus making the Annual Yield more attractive of 8.42%.
- Waterfall structured escrow mechanism with DSRA makes the Bond fully secured from investors perspective.
- From the consecutive 6 times cleanest city of India having an excellent track record of timely interest payment & sinking fund transfers on due dates.
- The proposed solar project is also registered in the Carbon Credit Mechanism, due to which the corporation will also get additional income of about 84 lakhs annually. Carbon credits fall into the category of innovation.
- Every bond holder will get the notification periodically for the number of solar unit generated. Will add value to the subscriber & bond holders contribution in green revolution. In addition to the attractive interest this Green would be an encouraging element.

INNOVATIVE FEATURE

इंदौर-311 ऐप से भी निगम का बांड खरीद सकेंगे आम लोग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. नगर निगम द्वारा जारी किया जा रहा ग्रीन बांड 10 से 14 फरवरी तक आमजन भी खरीद सकेंगे। आम आदमी इसे आसानी से खरीद सके, इसके लिए भी निगम ने और आसानी कर दी है। इसकी खरीदी के लिए निगम ने इंदौर-311 ऐप पर भी सुविधा मुहैया करवाई है। जहां से सीधे इस बांड को खरीदा जा सकेगा। बांड को लेकर बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के निवेशकों से भी चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को उनके पैसों के सुरक्षित होने और रिटर्न समय पर मिलने का आश्वासन दिलाया। भार्गव ने बताया, निगम ने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड की टीम के साथ मिलकर आम निवेशकों को आइएमसी ग्रीन बांड में निवेश के लिए इंदौर-311 ऐप पर भी सुविधा दी है। ऐप में आइएमसी ग्रीन बांड का ऑप्शन है, जिस पर जाकर आम जनता बांड खरीदी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

भार्गव ने बताया, निवेशक को यहां अपने पैन नंबर, डीमेट खाते और यूपीआइ की डिटेल देनी होगी। ये जानकारी देने के साथ ही सीधे आइपीओ के लिए अप्लाई हो जाएगा। जिस दिन आवेदन किया जाएगा, उसके कुछ घंटों बाद मोबाइल पर यूपीआइ मेंडेट को स्वीकार करने का संदेश आएगा, जिसे स्वीकार करने के बाद निवेशक के बैंक में अस्बा के माध्यम से इश्यू के लिए राशि ब्लॉक हो जाएगी। यदि निवेशक का डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहां से वह ऑनलाइन डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकेगा।

बांड के जरिए निगम जुटाएगा 244 करोड़

निगम जलूद से इंदौर तक पानी लाने के लिए लगने वाली बिजली के खर्चे को कम करने के लिए खरगोन जिले के सामराज व आशुखेड़ी में 60 मेगावाट क्षमता का पॉवर प्लांट लगाने जा रहा है। लगभग 300 करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट की 244 करोड़ की धनराशि निगम बांड के जरिए जुटाएगा। सोलर प्लांट की बिजली का उपयोग जलूद स्थित नर्मदा जल परियोजना के पंपों को संचालित करने में होगा, ताकि कम खर्च में नर्मदा का पानी इंदौर पहुंच सके। सोलर प्लांट से बिजली के बाद नर्मदा जल परियोजना के पंपों का बिजली बिल में लगभग साढ़े 4 करोड़ प्रतिमाह की कमी होगी।

देश में जन भागीदारी का संदेश

महापौर भार्गव ने निवेशकों को बताया, ग्रीन बांड से केवल धनराशि जुटाना ही उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इतनी राशि तो कोई भी बैंक लोन के रूप में दे सकता है। हमारा उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इंदौर की जन भागीदारी का यह संदेश पूरे देश में जाएगा, जो अन्य नगर निगम के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा।

10 लाख तक का कर सकेंगे निवेश

एक ग्रीन बांड का मूल्य 1 हजार रुपए है और यह 250-250 रुपए के चार भागों में है। रिटेल निवेशक इस बांड में न्यूनतम 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि का निवेश कर सकेंगे। बांड के भुगतान के लिए 3, 5, 7 व 9 वर्षों की अवधि तय की गई है। जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज हर 6 माह में भुगतान किया जाएगा।

मिलेगा बैंक डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज

महापौर ने निवेशकों को बताया, ग्रीन बांड में निवेशकों को 8.25 फीसदी की ब्याज दर ऑफर की जा रही है। यह दर बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक है।

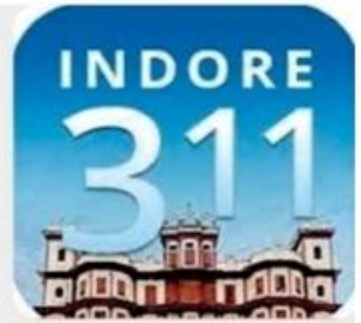

स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा बांड

आइएमसी ग्रीन बांड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। निवेशक यहां से बांड बेच सकते हैं। ग्रीन बांड का इश्यू पहले दिन सब्सक्राइब हो गया तो यथानुपात अलॉटमेंट दिया जाएगा। यदि पहले दिन पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

विभागवार बजट की समीक्षा शुरू

शहर के बजट की तैयारी शुरू

केंद्र सरकार के बजट के बाद अब नगर निगम में भी आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार को नगर निगम में विभागवार बजट की समीक्षा की गई।

निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट मद के संबंध में जनकार्य विभाग, जल यंत्रालय विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट विभाग, उद्यान विभाग, परिषद विभाग, प्राणी संग्रहालय विभाग, शहरी गरीबी उपशमन विभाग, विद्युत विभाग, वर्कशॉप विभाग, यातायात विभाग, योजना विभाग व अन्य विभागों की विभागवार आय व व्यय मद की समीक्षा की।

इसके साथ ही कुछ विभागों में बजट की राशि के प्रावधान को लेकर भी उन्होंने निर्देश जारी किए। वहीं इस दौरान उन्होंने वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की। वहीं उन्होंने राजस्व विभाग के साथ ही निगम के अन्य आय स्त्रोतों को बढ़ाने के संबंध में भी अफसरों को निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आयुक्त द्वारा बजट समीक्षा के दौरान निगम को प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए नगर निगम में सभी विभागों के बजट में संशोधन कर प्रस्ताव जल्द से जल्द देने के लिए कहा। वहीं इसके आधार पर बजट को अंतिम रूप देने के लिए कहा।

SUBSCRIPTION - SUMMARY

CATEGORY	ISSUE SIZE (CRORES)	SUBSCRIPTION FIGURE (CRORES)			SUBSCRIPTION PENDING (CRORES)	NO. OF TIMES
		LAST BIDDING DAY	TODAY	TOTAL		
INSTITUTION	61.00	229.35	0.00	229.35	(168.35)	3.76
CORPORATE	61.00	202.05	2.51	204.57	(143.57)	3.35
HNI	61.00	104.60	5.90	110.50	(49.50)	1.81
RETAIL	61.00	164.53	11.80	176.33	(115.33)	2.89
TOTAL	244.00	700.54	20.21	720.75	(476.75)	2.95
4,112 APPLICATION (APPROX)					BIDDING FIGURE AS ON :-	14 Feb 2023 17:01

Option	TOTAL SUBSCRIPTION FIGURE (CRORES)		
	LAST BIDDING DAY	TODAY	TOTAL
SERIES 1	700.54	20.21	720.75
TOTAL	700.54	20.21	720.75

BELL RING CEREMONY

PUBLIC ISSUE OF GREEN BOND

इंदौर ने रचा नया इतिहास : अब पांच नगर निगम भी जारी करेंगे बॉन्ड

देश का पहला रिटेलर ग्रीन बॉन्ड, सीएम ने दिया सोलर सिटी का चैलेंज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को सोलर सिटी बनने का चैलेंज मिला है। नगर निगम द्वारा जलूद प्लांट के लिए जारी किया गया ग्रीन बॉन्ड देश का पहला रिटेल ग्रीन बॉन्ड है। अब आम आदमी एक्सचेंज के जरिए शेयर की तरह इसकी खरीद-बिक्री कर सकेगा। अब तक जारी बॉन्ड इंस्टीटयूशनल खरीदी तक सीमित रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने बिजली के खर्च को कम करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर नवाचार किया है। मंगलवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बेल रिंगिंग सेरेमनी के दौरान गोंग (घंटा) बजा कर मुख्यमंत्री चौहान, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी ने ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्टेड कराने घोषणा की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व अन्य अतिथियों ने पारम्परिक रूप से बॉण्ड को लिस्टेड कराया।

ये तो इंदौर का पहला कदम : महापौर

कार्यक्रम के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस दौरान इसे पहला कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर की ब्रांड इमेज के कारण ये सफलता मिली है। यह नगर निगम का पहला और आखिरी बॉन्ड नहीं है, ये तो अभी शुरुआत मात्र है। अभी जलूद से नर्मदा जल के लिए सौर उर्जा से बिजली बना रहे हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी व निगमायुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रहें।

इंदौर ने 4 लाख कार्बन क्रेडिट अंक अर्जित किए

सीएम ने कहा, इंदौर देश का पहला शहर है, जिसने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड की लिस्टिंग 2018 में कराई थी। हमें इस साल मध्यप्रदेश के पांच और शहरों में यह लक्ष्य हासिल करना है। सीएम ने बताया कि अमरीका में स्थानीय निकाय बॉन्ड के जरिए 30 लाख करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। यदि निकाय किसी विजन पर काम करेंगे तो धन की कमी कभी नहीं होगी। इंदौर नगर निगम ने 4 लाख कार्बन क्रेडिट अंक अर्जित किए, इससे उसे करीब 9 करोड़ की आय हुई है।

जल्द करेंगे शुरुआत

कलेक्टर डॉ इलैयाराजा ने कहा, इंदौर को सोलर सिटी के लिए शुरूआत करेंगे। इंस्टीटयूशन स्तर पर रूफटॉप के जरिए सौर उर्जा लगा रहे हैं। घरों में सौर उर्जा का इस्तेमाल कैसे हो विकल्प देखेंगे।

PUBLIC ISSUE OF GREEN BOND

महानगर संस्करण · वर्ष - 04 · अंक - 186 इंदौर, बुधवार, 22 फरवरी 2023 · मूल्य - ₹2 · पृष्ठ - 8

लीक से हटकर सोचता है इंदौर - मुख्यमंत्री

इंदौर के महापौर विजनरी महापौर

इंदौर ग्रीन बॉण्ड एनएसई में लिस्टेड होने वाला देश का पहला शहर बना

सत्तावादी रिपोर्टर ▸ इंदौर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में इंदौर ने एक इतिहास रच दिया है। नवाचार करने में अव्वल रहने वाले भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने पब्लिक ग्रीन बॉण्ड को देश में लिस्टिंग कर विकास को नई दिशा दिखाई है। राजधानी के कुशा भाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित इंदौर की जमकर तारीफ़ की मुख्यमंत्री ने पुष्यमित्र भार्गव को विजनरी महापौर सम्बोधित करते हुए कहा की इंदौर लीड से हटकर सोचता है और करता है ग्रीन बॉण्ड जारी लेना कोई साधारण काम नहीं है यह धरती को बचाने का अभियान है इसमें इंदौर के लोगो की जनभागीदारी भी अनुकरणीय है मुझे इंदौर के लोगो पर गर्व है कि उन्होंने धरती को बचाने की दिशा में कदम उठाया है भरोसा हो तो पैसो कि कमी आड़े नहीं आती है यह इंदौर में साबित हुआ है इंदौर पूरे देश को राह दिखा सकता है इस साल प्रदेश के पाँच शहरों में हमे यह लक्ष्य हासिल करना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की में इंदौर को एक और काम देना चाहता हूँ जिस तरह साँची पूरी तरह सोलर सिटी बन रहा है उस दिशा में इंदौर एतिहासिक काम कर सकता है में और देश को राह दिखा सकता है इसलिए लोगो को जागरूक कर सोलर एनर्जी पर काम करे में बाक़ी शहर से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी इंदौर के साथ प्रतियोगिता करें और आगे आएं।

दुनिया के सपनों का शहर बना इंदौर : महापौर

इंदौर नगर निगम के ग्रीनबोंड की एनएसई में लिस्टिंग सेरेमनी के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर अब सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगो के सपनो का शहर बन गया है। सीएम के आशीर्वाद से हमे ये सफलता मिली है। सीएम के इस विजन के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।इंदौर की ब्रांड इमेज के कारण ये सफलता मिली है।यह पहला और आख़िरी बॉण्ड नही है अभी यह शुरुआत है कार्यक्रम में खजुराहो सांसद वी डी शर्मा ने भी इंदौर के जज़बे की तारीफ़ करते हुए कहा की महापौर पुष्यमित्र भार्गव और जनप्रतिनिधियों का यह प्रयास इंदौर को ऊँचाइयों पर ले जाएगा और बाक़ी शहरों को भी इस दिशा में काम लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

समय से आगे चलने वाला दौर है इंदौर : सांसद

सांसद श्री शंकर लालवानी ने इस अवसर पर कहा कि आज इंदौर के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है, ग्रीन बांण्ड, मान. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंदौर के एक दौर है, जो समय से आगे चलता है। मान. प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात कही थी, और इंदौर ने मान. मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 6 बार स्वच्छता का अवॉर्ड जीता है, इसके लिये इंदौर की जनता ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मान. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी के मिशन पर कार्य करेगा।

BENEFITS

- It will also connect the people of the city with the Municipal Corporation and will give a better investment option in comparison to other available options in the market and create a healthy ecosystem.

- This is the first initiative across the country which will make a deep impact on the brand image of the City and the State and attract more such investments in the state.

- It fulfil the Commitment of Central and State Government towards Green Energy and will help the city to become a "Carbon Neutral City".

- Able to prevent 1.26 Lakh Tonnes of Carbon Dioxide emissions equivalent to planting 16.2 Lakh trees every year.

INITIATIVES BY OTHER GOVT. INSTITUTIONS IN INDIA

- Pune Municipal Corporation: In 2017, Pune Municipal Corporation issued India's first municipal green bond, raising INR 2.5 billion (approximately USD 33 million) to fund sustainable transport projects, including the Pune Metro Rail project and the Bus Rapid Transit System.Greater

- Hyderabad Municipal Corporation: In 2020, Greater Hyderabad Municipal Corporation issued a INR 2.5 billion (approximately USD 33 million) green bond to fund water supply and sewerage projects.

- Lucknow Municipal Corporation: In 2021, Lucknow Municipal Corporation issued a INR 1 billion (approximately USD 13 million) green bond to finance solid waste management and wastewater treatment projects.

- Ahmedabad Municipal Corporation: In 2021, Ahmedabad Municipal Corporation issued a INR 2 billion (approximately USD 26 million) green bond to fund sustainable transport infrastructure, including the Ahmedabad Metro Rail project.

GREEN BOND INITIATIVE – GLOBALLY

- The Republic of France issued a €7 billion green bond in January 2021 to finance projects related to renewable energy, energy efficiency, and sustainable transportation.
- Bank of China issued a $3.03 billion green bond in November 2020 to support projects related to renewable energy, clean transportation, and pollution control.
- The European Investment Bank (EIB) issued a €600 million green bond in September 2020 to finance renewable energy and energy efficiency projects in Europe.
- Apple issued a $1.5 billion green bond in February 2019 to fund the company's clean energy initiatives, including renewable energy projects and energy-efficient buildings.
- The Republic of Indonesia issued a $1.25 billion green bond in February 2018 to finance projects related to renewable energy, energy efficiency, and sustainable transportation.

Thank you!

Indore Municipal Corporation